



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 18 अगस्त, 2009/27 श्रावण, 1931

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 12 अगस्त, 2009

**संख्या : वि०स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-26/2009.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक-10) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,  
गोवर्धन सिंह,  
सचिव ।

**हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) विधेयक, 2009**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के बुरे व्यवहार का निवारण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह 25 मार्च, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

**2. परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “शैक्षणिक संस्था” से कोई भी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से सहबद्ध या इस द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, तकनीकी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, पॉलिटेक्निक या संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं;

(ख) “प्रभारी अधिकारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, छात्रावास का प्रमुख (हैड), संकायाध्यक्ष, अध्यापन विभाग या संस्था का प्रमुख (हैड), महाविद्यालय का प्राधिकारी (अथॉरिटी), छात्रावास या केन्टीन का वार्डन अथवा प्रबन्धक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए), छात्र कल्याण अधिकारी या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष, शैक्षणिक संस्था का प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, वार्डन, प्रबन्धक या अध्यापक नियुक्त किया गया है; और

(ग) “रैगिंग” से ऐसा कोई कार्य, आचरण या व्यवहार अभिप्रेत है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों, पूर्व छात्रों या बाहरी व्यक्तियों की प्रभुतापूर्ण शक्ति को, नए भर्ती (प्रविष्ट) किए गए छात्रों या उन छात्रों पर, जिन्हें अन्य छात्रों द्वारा किसी प्रकार से कनिष्ठ समझा जाता है, उपस्थापित किया जाए और इसके अन्तर्गत ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कार्य या व्यवहार हैं,—

(i) जिनमें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हमला या धमकी अथवा बल का प्रयोग या अनुचित परिरोध अथवा रोक (रोध) अन्तर्वलित हो; या

(ii) जो ऐसे छात्रों की प्रास्थिति, गरिमा और सम्मान का अतिक्रमण करते हों; या

(iii) जिनसे छात्रों का उपहास और तिरस्कार हो तथा जिनसे उनका स्वाभिमान प्रभावित होता हो; या

(iv) जिनमें मौखिक गाली और छेड़छाड़ (अग्रेसन), अशिष्ट इशारे और अश्लील व्यवहार का समावेश हो ।

**3. रैगिंग का प्रतिषेध.**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी भी शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर या इसके बाहर, किसी भी रूप में रैगिंग नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

**4. कतिपय व्यक्तियों के रैगिंग की घटनाओं की जांच पड़ताल करने और रिपोर्ट करने के कर्तव्य.—**(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी शैक्षणिक संस्था का प्रभारी अधिकारी है या जो, उसमें अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने हेतु शैक्षणिक संस्था की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है या उससे पारिश्रमिक पाता है, रैगिंग की किसी भी घटना के होने पर तुरन्त कार्रवाई करने और विश्वविद्यालय की दशा में कुलपति या उस द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को या विश्वविद्यालय से भिन्न संस्था की दशा में शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) को उनकी पहचान, जो रैगिंग में लगे हों और घटना की प्रकृति की रिपोर्ट करने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) रैगिंग की प्रत्येक घटना में, जहां पीड़ित या उसके माता-पिता या संरक्षक या शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड), कार्रवाई के लिए संस्था की व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं होता है, वहां संस्थागत प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास बिना अपवाद के, प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की जाएगी ।

(3) संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने में विफलता या असावधानी या विमर्शित (जानबूझकर) विलम्ब को, संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा सदोष असावधानी समझा जाएगा ।

(4) यदि कोई पीड़ित या उसके माता-पिता या संरक्षक, पुलिस के पास सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करना चाहता है, तो इससे संस्थागत प्राधिकारी (अथॉरिटी) प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने की अपेक्षा से मुक्त नहीं होगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

**5. धारा 3 के अधीन अपराधों का दुष्प्रेरण.—**जो कोई भी शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड) या शैक्षणिक संस्था में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीधे तौर पर या मुख्यतः, पर्यवेक्षण का प्रभारी अधिकारी होने के नाते, जानबूझकर जांच-पड़ताल नहीं करता है और रिपोर्ट नहीं करता है या धारा 3 के अधीन अपराध करने में मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

**6. अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और शमनीय होना.—**इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा ।

**7. छात्र का निष्कासन.—**(1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष छात्र को शैक्षणिक संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निष्कासित या रैगिंग के कारण अन्यथा निष्कासित छात्र को, ऐसे निष्कासन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

**8. छात्र का निलम्बन.—**(1) जब कभी कोई भी छात्र या, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक या किसी शैक्षणिक संस्था का अध्यापक या प्रभारी अधिकारी, लिखित में रैगिंग की शिकायत (परिवाद) शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) को करता है, तो उस शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हैड), पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना, शिकायत प्राप्त होने के चौबीस घण्टों के भीतर इसकी जांच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया यह सही पाई जाती है, तो दोषी पाए गए छात्र को निलम्बित करेगा।

(2) जहां शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हैड) द्वारा जांच किए जाने पर यह साबित हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई सार नहीं है, तो वह तथ्य को लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

**9. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.**—राज्य सरकार लोक हित में, लिखित में आदेश द्वारा, उसमें अभिलिखित कारणों से शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसी संस्था द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधारण अनुदेश दे सकेगी और ऐसे अनुदेश के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) और हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4), जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का 14), चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2), ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3), राज्य में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 (1968 का 14), हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 14), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का 25) में किसी बात के होते हुए भी, रैगिंग के प्रतिषेध और उसके लिए दण्ड से सम्बन्धित अध्यादेश, परिनियम, विनियम, नियम, उप विधियां बनाने और उनमें संशोधन, ऐसे प्रारूप में और ऐसी अवधि के भीतर जैसी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के निदेश भी हैं।

**10. उपबन्धों का कतिपय विधियों के अल्पीकरण में न होना.**—इस अधिनियम के उपबन्ध, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17), हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4), जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का 14), चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2), ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3), राज्य में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 (1968 का 14), हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 14), सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का 25) के अधीन विरचित परिनियमों के अल्पीकरण में नहीं, अपितु उनके अतिरिक्त होंगे।

**11. नियम बनाने की शक्ति.**—राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

**12. नियमों और आदेशों का रखा जाना.**—धारा 9 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 11 के अधीन बनाए गए नियम, जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा जाता है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा, यथास्थिति, उस नियम या आदेश में कोई परिवर्तन करती है या यह विनिश्चय करती है कि नियम या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, नियम या आदेश तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, यथास्थिति, नियम या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**13. 2009 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) 2009 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव के समग्र विकास के लिए शिक्षा बुनियादी कारक है। राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ शिक्षा की ओर और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की बढ़ती हुई घटनाओं से ऐसी संस्थाओं में कनिष्ठ (जूनियर) छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं। हाल ही में टांडा मैडिकल कॉलेज, धर्मशाला में रैगिंग की भयावह घटना, जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, ने शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का घिनौना (बदतरीन) चेहरा दिखा दिया है। रैगिंग का व्यवहार (प्रथा) न केवल मानव प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी है अपितु छात्रों के हित और अनुशासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसी अनुशासनहीनता ने उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर दिया है तथा कल्पना में भी अनुशासनहीनता को बर्दाशत नहीं किया जा सकता। रैगिंग ने, महिला छात्रों सहित, नए छात्रों को अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का पात्र बनाने का रूप ले लिया है जो अपजनित होकर यहां तक कि शारीरिक हिंसा में भी बदल गई है।

इसलिए इस सामाजिक खतरे से प्रतिरोध (जूझने) के आशय से राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के बुरे व्यवहार पर नियन्त्रण करने और रोक लगाने तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए तुरन्त विधि अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 की सिविल अपील संख्या: 887 नामतः यूनिवर्सिटी ऑफ केरल बनाम काउन्सिल, प्रिंसिपल, कॉलेजिज केरल एण्ड अदरज, में अपने आदेश तारीख 11 फरवरी, 2009 में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए तुरन्त पग उठाने हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को कतिपय निदेश जारी किए हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के बुरे व्यवहार (कुप्रथा) के निवारण का उपबन्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है। विधान, शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की जांच, दोषी पाए गए छात्रों के निलम्बन और निष्कासन का उपबन्ध करता है और संस्था के प्राधिकारियों (अथॉरिटीज) तथा माता-पिता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर (दर्ज) करने का उपबन्ध करता है और भयोपरापी दण्ड और जुर्माने अर्थात्, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों के लिए उपबन्ध करता है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्यांक 1) 25 मार्च, 2009 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे उसी तारीख को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। अब इस अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं।

ईश्वर दास धीमान,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला  
तारीख....., 2009

**वित्तीय ज्ञापन**

इस विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

विधेयक के खण्ड 9 और 11 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः निदेश देने और नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT****Bill No. 10 of 2009****THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PROHIBITION OF RAGGING) BILL, 2009****(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)****A****BILL**

*to provide for prevention of the evil practice of ragging in educational institutions in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on 25<sup>th</sup> day of March, 2009.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “educational institution” means any University, any College affiliated to or maintained by the University, any school imparting secondary education, any school, Polytechnic or institution imparting technical education and includes such other institutions as may be notified by the State Government in the Official Gazette;

(b) “Officer-in-Charge” means and includes person appointed as the Principal of College, Head of Hostel, Dean of Faculty, Head of Teaching Department or the institution, the

authority of the College, Warden or Manager (by whatever name called) of Hostel or canteen, the Student Welfare Officer or the Librarian of the College and University Library, Principal, Headmaster, Warden, Manager or teacher of the educational institution; and

- (c) “ragging” means any act, conduct or practice by which dominant power of senior students, former students or outsiders, is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior by other students and includes individual or collective acts or practices which—
- (i) involve physical or psychological assault or threat or use of force or wrongful confinement or restraint; or
  - (ii) violate the status, dignity and honour of such students; or
  - (iii) expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem; or
  - (iv) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

**3. Prohibition of ragging.**—(1) No person shall practise ragging in any form, within or outside the premises of an educational institution.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

**4. Duties of certain persons to check and report incidents of ragging.**—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, every person who is the Officer-in-Charge of the educational institution or who is in the service or pay of or remunerated by the educational institution to do any work assigned to him in connection with the maintenance of discipline therein, shall be bound to take immediate action on the occurrence of any incident of ragging and to make report to the Vice-Chancellor or to any other officer authorised by him, in case of the University, or the Head of the educational institution, in case of the institution other than the University, the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.

(2) Every single incident of ragging where the victim or his parents or guardian or the Head of educational institution is not satisfied with the institutional arrangement for action, a First Information Report shall be lodged without exception by the institutional authorities with the local police authorities.

(3) Any failure on the part of the institutional authority or negligence or deliberate delay in lodging the First Information Report with the local police, shall be construed to be an act of culpable negligence on the part of the institutional authority.

(4) If any victim or his parent or guardian intends to lodge First Information Report directly with the police that shall not absolve the institutional authority from the requirement of lodging the First Information Report.

(5) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3), shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

**5. Abetment of offences under section 3.**—Whoever being a Head of educational institution or an officer, directly or primarily in-charge of supervision for the proper maintenance of discipline in the educational institution, knowingly omits to check and report or connives or abets the commission of the offence under section 3, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

**6. Offences to be cognizable, non-bailable and compoundable.**—Every offence under this Act shall be cognizable, non-bailable and compoundable with the permission of the court.

**7. Expulsion of student.**—(1) Any student convicted of an offence under this Act shall be expelled from the educational institution.

(2) Student expelled under sub-section (1) or expelled otherwise on account of ragging shall not be admitted in any other educational institution for a period of three years from the date of order of such expulsion.

**8. Suspension of student.**—(1) Whenever any student or, as the case may be, the parents or guardian or a teacher of an educational institution or an Officer-in-Charge makes a complaint, in writing, of ragging to the head of the educational institution, the head of that educational institution shall, without prejudice to the foregoing provisions, within twenty four hours of the receipt of the complaint, enquire into it and, if, prima facie, it is found true, suspend the student found guilty.

(2) Where, on enquiry by the head of the educational institution, it is proved that prima facie there is no substance in the complaint received under sub-section (1), he shall intimate the fact, in writing, to the complainant.

**9. Power of the State Government to give directions.**—The State Government may, in public interest, by order in writing for reasons to be recorded therein, give to the educational institutions general instructions to be followed by such institutions and such instructions may, notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh University Act, 1970 (17 of 1970) and the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1987), the Jaypee University of Information Technology Act, 2002 (14 of 2002), the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009), the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (3 of 2009), any University established by Law in the State in private and public sector, the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968), the Himachal Pradesh Board of Technical Education Act, 1986 (14 of 1986), the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (25 of 2006), include directions to make or amend any ordinances, statutes, regulations, rules, bye-laws relating to the prohibition of and the punishment for ragging, in such form and within such period as may be specified in such order.

**10. Provisions not to be derogatory to certain laws.**—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and the statutes framed under the Himachal Pradesh University Act, 1970 (17 of 1970), the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1987), the Jaypee University of Information Technology Act, 2002 (14 of 2002), the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009), the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (3 of 2009), any University established by Law in the State in private and public sector, the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968), the Himachal Pradesh Board of Technical Education



Act, 1986 (14 of 1986), the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) and the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (25 of 2006).

**11. Power to make rules.**—The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

**12. Laying of rules and orders.**—Every order issued under section 9 and rules made under section 11 shall be laid, as soon as may be after it is issued or made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule, or as the case may be, in the order, or decides that the rule or the order, as the case may be, should not be issued or made, the rule or as the case may be, the order, shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or as the case may be, under that order.

**13. Repeal of Ordinance No. 1 of 2009 and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibitions of Ragging) Ordinance, 2009 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor for overall development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the Country require more attention towards education, but with the rising incidents of ragging in the educational institutions, the junior students feel unsecured in such institutions. The recent shocking incident of ragging in Tanda Medical College, Dharamsala, where a student has died, has shown the worst face of ragging in the educational institutions. The practice of ragging is not only subversive of human dignity but also prejudicially affects the interest of the students and the discipline in such institutions. This indiscipline has polluted the healthy environment needed for good education and by no stretch of imagination indiscipline can not be tolerated. The ragging has taken the form of subjecting freshers including female student to inhuman and humiliating treatment degenerating even into physical violence.

Thus, in order to combat this social menace, it has become immediate need to enact a law to maintain discipline and to curb and control the evil practice of ragging in educational institutions in the State. The Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 887 of 2009 titled as University of Kerala Vs Council, Principal, Colleges, Kerala and others vide its order dated 11<sup>th</sup> February, 2009 has also issued certain directions to the Central and the State Governments to take immediate steps to curb the menace of ragging in the educational institutions. Thus, in view of the above, it was decided to enact a law which may provide for prevention of evil practice of ragging in educational institutions in the State of Himachal Pradesh. The legislation provides for checking of ragging in the educational institutions, suspension and expulsion of students found guilty and provisions for registration of FIR by the institutional authorities and by the parents and provisions of deterrent punishment and fine which may extend up-to three years of imprisonment and fine up-to fifty thousand rupees or with both.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the action was required to be taken urgently, therefore, the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 1 of 2009) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 25-03-2009 and was published in Rajpatra Himachal Pradesh on the same date. Now, the Ordinance is required to be replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**ISHWAR DASS DHIMAN,**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :  
The....., 2009.

### FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall be enforced through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure from the State Exchequer.

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 9 and 11 of the Bill seek to empower the State Government to give directions and to make rules respectively for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

### हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 12 अगस्त, 2009

**संख्या वि० स०-लैज-गवरनमैट बिल/1-25/2009.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बद्धी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसिज़ एण्ड टेक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक-12) जो आज दिनांक 12 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,  
गोवर्धन सिंह,  
सचिव।

## बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी की स्थापना, निगमन और विनियमन करने और उसके क्रियाकलापों को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

**2. परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “प्रबन्ध बोर्ड” से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ख) “परिसर” (कैम्पस) से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;
- (ग) “दूरवर्ती शिक्षा” से संचार, अर्थात् प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;
- (घ) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;
- (ङ) “फीस” से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;
- (च) “सरकार” या “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “शासी निकाय” से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;
- (ज) “उच्चतर शिक्षा” से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;
- (झ) “छात्रावास” से विश्वविद्यालय, या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;
- (ञ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ट) “परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र” से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर ( कैम्पस ) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

- (ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्निध सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;
- (ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सेंटर फॉर एडवांसड स्टडीज़ इन इन्जीनियरिंग (सी0ए0एस0ई0), नई दिल्ली अभिप्रेत है;
- (थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;
- (प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और
- (फ) "विश्वविद्यालय" से बर्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग साइंसिज़ एण्ड टेक्नोलॉजी बर्दी अभिप्रेत है।

### 3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;
- (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;
- (घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;
- (ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;
- (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;

(छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमो, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और

(ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र स्थापित करना ।

**4. निगमन.—**(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर बददी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टेक्नोलॉजी, बददी के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

**5. शक्तियां और कृत्य.—**(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित, विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबंध करना;
- (ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;
- (iii) निवेश—बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;
- (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यक्षीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;
- (v) मानद उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना;
- (vi) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;
- (ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;
- (x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;
- (xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;

- (xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;
- (xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ़ ऐक्सीलेंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;
- (xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहकार करना;
- (xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;
- (xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हो, कोई करार करना;
- (xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;
- (xix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;
- (xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;
- (xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;
- (xxiv) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;
- (xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;
- (xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;

(xxvii) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ-कैम्पस केन्द्र, ऑफ-शोर केन्द्र और विद्या केन्द्र स्थापित करना;

(xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना;

(2) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो के साथ जाति, वर्ग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

**6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.**—विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

**7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.**—विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी।

**8. विन्यास निधि.**—(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रूपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जाएगी।

**9. साधारण निधि.**—विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;

(घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

**10. साधारण निधि का उपयोजन.**—साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किसी भविष्य निधि अभिदाय, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;
- (ग) करों या स्थानीय उदग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;
- (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उसके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;
- (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा परीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;
- (झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;
- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और
- (ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाए, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

**11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.**—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) रजिस्ट्रार;



(iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और

(v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

**12. कुलाधिपति.**—(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;

(ख) कुलपति को नियुक्त करना;

(ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

**13. कुलपति.**—(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है

या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बन्धित प्राधिकरण से, विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

**14. रजिस्ट्रार.—**(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार/संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य—सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

**15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.—**(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

**16. अन्य अधिकारी.—**(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

**17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—**विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

**18. शासी निकाय.—**(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :—

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;
- (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;
- (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और
- (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा—उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;
- (ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

**19. प्रबन्ध बोर्ड.—**(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) कुलपति;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और
- (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।

**20. विद्या परिषद्.—**(1) विद्या परिषद् में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(3) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

**21. अन्य प्राधिकरण.—**विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**22. निरर्हताएं.—**कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या

(ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।

**23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—**विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

**24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—**यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करती है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है सदस्य होता।

**25. समितियां.—**(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारी ऐसे निर्देश के निबन्धनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**26. प्रथम परिनियम.—**(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थातः—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किए जाए;

- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;
- (ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थता के लिए प्रक्रिया;
- (छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ज) छात्रों को शिक्षा फीस (ट्यूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध;
- (झ) सीटों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध;
- (ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

**27. पश्चात्पूर्ति परिनियम.—**(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्पूर्ति परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;
- (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;
- (घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;
- (ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और
- (झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3). प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और अनुदेशों के मानदण्डों, शिक्षा और परीक्षा को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

**28. प्रथम अध्यादेश.—**(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अधीन, प्रबंध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमों, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और
- (ट) ऐसे सभी विषय, जिनका इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय, को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

**29. पश्चात्तवर्ती अध्यादेश.—**(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेशों को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

**30. विनियम.**—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

**31. प्रवेश.**—(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी ।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

**32. फीस संरचना.**—(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन प्रवहित (प्रदान) करेगी:

परन्तु यदि सरकार एक मास के भीतर अनुमोदन प्रवहित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को जारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि प्रस्तावित फीस,—

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्—

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

**33. परीक्षाएं.**—प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात् (अपश्चात्), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य—शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

**स्पष्टीकरण:**—परीक्षाओं की अनुसूची से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

**34. परिणामों की घोषणा.**—(1) विश्वविद्यालय, अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

**35. दीक्षांत समारोह.**—विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिणियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

**36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.**—विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

**37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।



**38. वार्षिक रिपोर्ट.—**(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।

**39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.—**(1) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित, वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उदभूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी।

**40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.—**(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, कुलपति से परामर्श के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिश का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

**41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.—**(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पंद्रह वर्ष के भीतर विघटित कर देता है तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लिंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी।

**42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियाँ:—**(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे ।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियाँ होंगी और वह इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड के सभी कर्तव्यों के अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियाँ, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियाँ, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा ऐसी तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे।

**43. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और

(ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

-----

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा वह बुनियादी कारक है जो मानव के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करती हैं। विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को, आधुनिक और परिष्कृत सुविधाओं सहित, खोलना अनिवार्य है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ-साथ राज्य में नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि को खोलने की आवश्यकता जोर पकड़ रही है।

देश में अन्य राज्यों की तरह सोसाइटियाँ, प्राइवेट सेक्टर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव (निवेदन) कर रही हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार को ऐसे पक्षकारों से, राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने

के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सैंटर फॉर एडवांसड स्टडीज़ इन इन्जीनियरिंग, नई दिल्ली जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, से भी प्राइवेट विश्वविद्यालय नामतः "बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी, बद्दी सोलन" स्थापित करने बारे प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात् सरकार द्वारा 22 अगस्त, 2007 को "आशय पत्र" जारी किया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरमानों का बनाए रखना) विनियम, 2003 के उपबन्धों के दृष्टिगत प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय राज्य द्वारा अलग से बनाए गए अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप होगा । प्राइवेट विश्वविद्यालय न केवल ऐकिक विश्वविद्यालय होना चाहिए बल्कि उसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षण और विस्तारी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की अपेक्षाओं और मानदण्डों को पूरा करने के आशय से विधान लाने का विनिश्चय किया गया है जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना, निगमन और विनियमन का उपबन्ध करने के लिए है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,  
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला

तारीख \_\_\_\_\_, 2009

### वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक राज्य में बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ़ इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर में करने का उपबन्ध करता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर कोई वित्तीय व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 43 और 26 राज्य सरकार को क्रमशः विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम बनाने के लिए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड 27 और 28 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय के क्रमशः पश्चात्तवर्ती परिनियम और अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**BILL No. 12 of 2009**

## **THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2009**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to provide for establishment, incorporation and regulation of Baddi University of Emerging Sciences and Technology in the State for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the State Government, by notification in the Official Gazette appoint.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Board of Management” means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;
- (b) “campus” means the area of University within which it is established;
- (c) “distance education” means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;
- (d) “employee” means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (e) “fee” means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;
- (f) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) “Governing Body” means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;
- (h) “higher education” means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
- (i) “hostel” means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such by the University;
- (j) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
- (k) “off campus centre” means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University’s complement of facilities, faculty and staff;
- (l) “Official Gazette” means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (m) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

- (n) “regulating body” means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Indian Research etc. and includes the Government;
- (o) “section” means a section of this Act;
- (p) “sponsoring body” means the Centre for Advanced Studies in Engineering(CASE), New Delhi, registered under the Society Registration Act,1860;
- (q) “State” means State of Himachal Pradesh;
- (r) “statutes”, “ordinances” and “regulations” mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;
- (s) “student” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;
- (t) “study centre” means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;
- (u) “teacher” means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and
- (v) “University” means Baddi University of Emerging Sciences and Technology, Baddi.

**3. The objects of the University.**—The objects of the University shall include,—

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;
- (b) to establish facilities for education and training;
- (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;
- (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;
- (e) to establish campus in the State;
- (f) to establish examination centres;
- (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and
- (h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

**4. Incorporation.**—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic

Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Baddi University of Emerging Sciences and Technology, Baddi, District Solan, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall situate and have its head quarter at Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh.

**5. Powers and functions.**—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

- (i) to provide for instructions including the method of distant education in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension education;
- (ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;
- (iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;
- (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (v) to confer honorary degrees or other academic distinctions;
- (vi) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;
- (vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;
- (viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition;
- (ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the Colleges;
- (xi) to determine the criterion for admission into the University or its Colleges;
- (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;
- (xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and

- research, including distance education subject to the University Grants Commission Act and the regulations made thereunder;
- (xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;
  - (xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act and the regulations made thereunder;
  - (xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;
  - (xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;
  - (xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;
  - (xix) to receive donations and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within and outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;
  - (xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
  - (xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;
  - (xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University;
  - (xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;
  - (xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of the Act;
  - (xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;
  - (xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;
  - (xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centers, off-shore campus, study centres as per the instructions issued by the State Government, Central Government and University Grants Commission from time to time;
  - (xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions;



(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

**6. University to be self-financed.**—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

**7. No Power of Affiliation.**—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

**8. Endowment Fund.**—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crores rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilised for the development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

**9. General Fund.**—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:—

- (a) fees and other charges received by the University;
- (b) any contribution made by the sponsoring body;
- (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;
- (d) bequests, donations, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the University.

**10. Application of General Fund.**—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

- (a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the university and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;
- (b) for the expenses to be incurred by the university for services availed including services like electricity, telephone etc.;
- (c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;
- (d) for up keeping of the assets of the University;
- (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;

- (f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;
- (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;
- (h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;
- (i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (j) for the purpose of movable and immovable assets;
- (k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and
- (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

**11. Officers of the University.**—The following shall be the officers of the University, namely:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

**12. The Chancellor.**—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) the Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

- (a) to call for any information or record;
- (b) to appoint the Vice-Chancellor;
- (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and
- (d) such other powers as may be specified by the Statutes.

**13. The vice-Chancellor.**—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section(7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity, thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons

therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

**14. The Registrar.**—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

**15. The Chief Finance and Accounts Officer.**—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

**16. Other officers.**—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

**17. Authorities of University.**—The following shall be the authorities of the University, namely:—

- (i) the Governing Body;
- (ii) the Board of Management;
- (iii) the Academic Council; and
- (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

**18. The Governing Body.**—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;
- (d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;
- (e) two persons, nominated by the Government; and
- (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

(3) The Governing Body shall have the following powers, namely:—

- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
- (b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
- (c) to approve the budget and annual report of the University;
- (d) to lay down the policies to be followed by the University;
- (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts; and
- (f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

**19. The Board of Management.**—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
- (c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and
- (d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

**20. The Academic Council.**—(1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

**21. Other authorities.**—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

**22. Disqualifications.**—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,—

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
- (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
- (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

**23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.**—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

**24. Filling of casual vacancies.**—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

**25. Committees.**—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

**26. The first statutes.**—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;

- (d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;
- (e) the terms and conditions of service of employees of the University;
- (f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
- (i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
- (j) provisions regarding fees to be charged from the students; and
- (k) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

**27. The subsequent statutes.**—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) creation of new authorities of the University;
- (b) accounting policy and financial procedure;
- (c) representation of teachers in the authorities of the University;
- (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation of posts and procedure for abolition of posts;
- (g) revision of fees;
- (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and
- (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the First Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

**28. The first ordinances.**—(1) Subject to the provisions of this Act or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;
- (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and
- (k) all other matters which by this Act or statutes made thereunder are required to be provided for by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.



**29. The subsequent ordinances.**—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

**30. Regulations.**—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

**31. Admissions.**—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

**32. Fee structure.**—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within one month from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within one month, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is—

(a) sufficient for generating—

(i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

- (ii) the savings required for the further development of the University; and
  - (b) not unreasonably excessive.
- (3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.
- (4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

**33. Examinations.**—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

*Explanation.*—Schedule of Examination means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

**34. Declaration of results.**—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

**35. Convocation.**—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

**36. Accreditation of the University.**—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

**37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.**—Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

**38. Annual report.**—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

**39. Annual accounts and audit.**—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

**40. Powers of the Government to inspect the University.**—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, after consultation with the Vice-Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

**41. Dissolution of the University by the sponsor body.**—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before fifteen years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

**42. Special powers of the Government in certain circumstances.**—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
- (c) requisitioning any public record from any court or office; and
- (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section(8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

**43. Power to make rules.**—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and

(b) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**44. Power to remove difficulties.**—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Education is the basic factor which plays a very important role in the all round development of human beings. The socio-economic conditions of the State and the country require more attention towards education. With a view to accelerate the pace of development, it is imperative to open more educational institutions with modern and sophisticated facilities. With each passing day, the need for opening new Colleges, Universities, Professional Colleges/Institutions etc. is gaining momentum in the State.

Like other States in the country, Societies in the private sectors have been approaching the Government for establishing Universities. Many State Governments have allowed the setting up of private Universities. The State Government has been receiving many applications from such parties to establish private Universities in the State. Centre for Advanced Studies in Engineering, New Delhi, registered under the Societies Registration Act-1860 had also submitted a proposal to establish a private university namely, “Baddi University of Emerging Sciences and Technology, Baddi, Solan” and after detailed examination the Government had issued “Letter of Intent” on 22<sup>nd</sup> August, 2007.

In the light of the provisions of University Grants Commission (Establishment and Maintenance of Standards of Private Universities) Regulations, 2003, each private University must be established by a separate State Act and shall conform to the provisions of University Grant Commission Act. Not only that, a private university must be a unitary university having adequate facilities for teaching, research, examination and extension activities. Thus, in order to fulfil the requirement of University Grant Commission Act and the norms, it has been decided to bring a legislature which may provide for establishment, incorporation and regulation of Baddi University of Emerging Sciences and Technology in the State for higher education.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**ISHWAR DASS DHIMAN,**  
**Minister-in-Charge.**

**SHIMLA:**  
**The.....2009.**

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

The Bill seeks to provide for the establishment of Baddi University of Emerging Sciences and Technology in the State solely in the private sector. The provisions of this Bill, if enacted, shall not involve any financial expenditure on the State Exchequer.

### **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clauses 43 and 26 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act and to make first statutes of the University respectively. Further clauses 27 and 28 of the Bill seek to empower Board of Management of the University to make subsequent statutes and first ordinance of the University, respectively. The proposed delegations of powers are essential and normal in character.

**आबकारी एवं कराधान विभाग**

अधिसूचना

12 अगस्त, 2009

संख्या: ई0 एक्स0एन0-एफ(6)-1/2003-पी0एफ-1.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन में निम्नलिखित स्थानों पर पथकर का संग्रहण करने के लिए नये पथकर नाके (टोल-बैरियर) तुरन्त प्रभाव से स्थापित करने के आदेश देती हैं.—

| जिला का नाम | स्थान का नाम जहां पथकर नाका (टोल बैरियर) खोला जाना है  |
|-------------|--|
| सोलन        | 1. नानकपुर-कालू झण्डा मधाला रोड मधाला चौक पर<br>2. रामपुर जग्गी ट्रक युनियन बरोटीवाला रोड (ट्रक युनियन के नजदीक) |

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव।

-----

*(Authoritative English text of this department notification NoEXN-F (6) 1/2003-PF-I dated 12-8-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)*

**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****NOTIFICATION**

12th August, 2009

**No.EXN-F (6) 1/2003-PF-I.**—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No.9 of 1975), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of new toll barriers on the following places in district Solan with immediate effect for the collection of toll.—

| Name of District | Name of place at which toll barrier os to be opened   |
|------------------|---|
| Solan            | 1. Nanakpur-Kalu Jhanda Madala Road (At Madala Chowk).<br>2. Rampur Jaggi Truck Union Barotiwala Road (Near Truck Union). |

By order,  
Sd/-  
Pr. Secretary.

**H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS  
FAIRLAWNS, SHIMLA-171012**

**NOTIFICATION**

*Shimla-12, the 31st July, 2009*

**No. HIPA (EXAM)-12/75-15.**—In exercise of the powers conferred by Rule 24(2) of H.P. Board of Departmental Examination Rules, 1997 as notified by Government of Himachal Pradesh, Department of Training & Foreign Assignments *vide* Notification No. Per (Trg)B(12)-40/95 fated 13-3-1997, the Board of Departmental Examinations Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission hereby inserts new syllabus for the Departmental Examination in respect of the Social Justice & Empowerment department as per Appendix-I attached hereto. The Board further orders that on the date of issue of the present Notification, the syllabus as mentioned in Appendix-I shall stand amended and replace the existing syllabus for Departmental Examinations in respect of the department as detailed in Schedule D attached to the Departmental Examination Rules, 1997, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(i) These Rules shall be called the Himachal Pradesh Departmental Examinations (Eighth Amendment) Rules, 2009.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Rule 24(1) Paper and Syllabus.**—For the existing provisions against sub-rule (I) of Rule 24 the Syllabus for the Departmental Examinations of category of officers of the Social Justice & Empowerment department given in the Schedule D shall be inserted by amended syllabus of Paper(s) of Department: APPENDIX 'I' to these rules.

By Order,  
Sd/-  
Secretary.

विभागीय परीक्षा बोर्ड  
फेयरलॉन्ज, शिमला-171012

अधिसूचना

शिमला-12, 31 जुलाई, 2009

**संख्या हिपा (परीक्षा)-12/75-15.**—हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 के उप-नियम 24 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं समनुदेशन) द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का. 1 (प्रशिक्षण) बी (12)-40/95, दिनांक 13-3-1997 द्वारा अधिसूचित किया गया है, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड एतद द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, विभागीय परीक्षा नियम 1997 में हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पाठ्यक्रम में निम्नानुसार संशोधन तथा प्रतिस्थापित संलग्न अनुसूचि D पर वर्णित विभागीय परीक्षा के पुराने पाठ्यक्रम को परिशिष्ट-1 पर वर्णित सम्बन्धित विभाग के पाठ्यक्रम को राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रतिस्थापित एवं संशोधित समझा जाए ।



**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा (अष्टम संशोधन) नियम 2009 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. नियम 24(1) का संशोधन पर्व तथा पाठ्यक्रम.—**नियम 24 के उप नियम 1 के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम जोकि अनुसूचि D में दिए गए हैं, को, विभाग के संशोधित पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 जोकि नियमों में परिशिष्ट किए गए हैं द्वारा अन्तः स्थापित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
सचिव ।

### **Paper No. 3 Welfare**

1. Integrated Child Development Services Scheme, its origin, objectives and monitoring tools of ICDS.
2. National Nutrition Policy, Strategies to arrest malnutrition, role of micro-nutrients, anemia among women and children, role of sanitation and hygiene in over-all health strategies.
3. National Policy on children and Child Action Plan.
4. Social Legislations relating to children such as J.J.(care & protection) Act, Child Marriage Prohibition Act.
5. Various Institutions such as Bal/Balika Ashrams, Juvenile Homes, children Homes etc.
6. National Women Empowerment Policy- 2001, its components and monitoring mechanism.
7. Social Legislations relating to Women such as Immoral Trafficking Prohibition Act, 1956, Dowry Prohibition Act, 1961, Mechanism prescribed for Protection of Women from Sexual Harassment at work places, Act for Protection of Women from Domestic Violence, 2005 and the Rules of this Act, H.P. Registration of Marriages Act, 1996 and Rules, 2004.
8. National/State Commission for Women.
9. H.P. Mahila Vikas Nigam.
10. Central/State schemes for Women and children.
11. Rajya Mahila Samiti.
12. Schemes relating to girl child including Balika Samridh Yojana, Kishori Shakti Yojana, P.C.& P.N.D.T. Act.

### **Paper No. 4 Welfare (Backward Classes Sector) :**

1. Constitutional safeguards for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.

2. Major Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes and Minorities in Himachal Pradesh and their problems, measures and solutions.
3. Social legislation- Protection of Civil Rights Act, 1955 & Rules 1977, Scheduled Caste/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 & Rules 1995, H.P. Land Regulation Act 1968- Implementation thereof.
4. National Commission for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ National Commission for Backward Classes/ National Commission for Minorities/ National Commission for Linguistic Minorities / State Commission for Backward Classes- Recommendations thereof.
5. H.P. Vidhan Sabha Committee for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes.
6. Central/State sponsored schemes for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/OBCs/Minorities and their impact and implementation.
7. Scheduled Caste Sub Plan History, Impact and implementation, monitoring & evaluation system.
8. Constitution, function and role of District Welfare Committee.
9. H.P Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Corporation/H.P BCs Finance & Development Corporation/ H.P. Minorities Finance & Development Corporation- function and Programmes.
10. National Scheduled Caste Development Corporation, National Scheduled Tribe Development Corporation- Function and Programmes.
11. State Level Welfare Boards- Scheduled Castes/ Other Backward Classes/ Minorities/ Labana/ Kabirpanthi/ Gorkha- Constitution, functions, important decisions etc.
12. Tribal Areas in Himachal Pradesh and their topographical conditions of tribal Districts viz Kinnaur, Lahaul & Spiti and Chamba (Pangi & Bharmour).
13. Tribal Sub Plan- Concept, Impact and implementation, Monitoring & evaluation system.
14. Single line Administration in Tribal Areas, Tribal Advisory Council and Project Advisory Committee- Administration Structure, Policy & Powers and
15. Impact of schemes for Welfare of Scheduled Tribes.

#### **Paper No. 5 Welfare (Social Defence):**

##### **(1) Disability Sector:-**

- Disability its concept, types of disability, early detection of disabilities, prevention of disabilities and rehabilitation. Procedure for assessment of disabilities and Issuing of Identity Cards to Persons with Disabilities and facilities after availing disability identity card.

##### **Legislation:-**

- The Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 & rules made there under,

- National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral, Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999,
- The Rehabilitation Council Act of India 1992.

**Programmes, policies relating to persons with disabilities:-**

- Various central/ state sponsored schemes for Persons with Disabilities- National Handicapped Finance & Development Corporation- Functions and Programmes. Impact and implementation of schemes and problems, measures and solutions.
- National Policy for Person with Disabilities.
- Special schools for special children in Himachal Pradesh.

**(II) Older person:-**

- Social Security concept, state social security pension schemes- implementation and impact thereof.
- Social Security for aged- Nation Social Assistance Programme, Annapurna.
- Institutional and non institutional services for the aged including state/ centrally sponsored schemes.
- Legislations- The H.P. maintenance of Parents and Dependents Act 2001 and rules 2002 – implementation thereof.
- National Policy for Older persons.

**(III) Drug Abuse and Alcoholism:-**

- Extent of problem in India and Himachal Pradesh, causes, prevention and rehabilitation.
- Narcotic control strategy- action plan of Ministry of Social Justice & Empowerment.
- State/Central schemes for the prevention of drug abuse and alcoholism.

**(IV) Probation Services:-**

- History and concept, role of department of Social Justice & Empowerment.
- Legislation-
- The Probation of Offenders Act, 1958
- The H.P. Prevention of Beggary Act, 1979 and Rules 1980.
- The H.P. Good Conduct Prisoners Probation Release Act, 1968,

**(V) Beggary:-**

- Extent of problem, causes, consequences and its prevention.
- Legislation- The H.P. Prevention of Beggary Act, 1979 and Rules 1980.

**(VI) NGOs Sector:-**

- Role of NGOs in the changing scenario particularly in social sector.
- H.P. Grant-in-Aid to Voluntary organizations, Rules 1981- implementation of programmes there under.
- H.P. Child Welfare Council,
- Central Social Welfare Board, State Social Welfare Board- function and structure, Other Voluntary Organization- constitution, functions, Registration Procedure etc.

**विभागीय परीक्षा बोर्ड  
फेयरलॉन्ज, शिमला-171012**

अधिसूचना

शिमला-171012, 24 जुलाई, 2009

**संख्या हिपा (परीक्षा)-21/76-5.**—भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा/ हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा आवकारी एवं कराधान विभाग के आवकारी एवं कराधान निरीक्षक, जिनके लिए विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है, के लिए इस का आयोजन अनुबन्ध “क” के अनुसार हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलॉन्ज, शिमला-171012, द्वारा दिनांक 5-11-2009 से 13-11-2009 तक आयोजित की जा रही है उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पर्चा संख्या-1 का आयोजन शिमला के अलावा मण्डी तथा धर्मशाला में भी किया जाना है । इन परीक्षाओं का आयोजन हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 जोकि समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अर्न्तगत किया जायेगा ।

अतः समस्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः का सत्र ठीक 10.00 बजे तथा सांय का 2.00 बजे बाद दोपहर आरम्भ होगा । जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हों वे अपने आवेदन पत्र निधारित प्रपत्र पर दो सत्यापित पास पोर्ट साईज फोटोग्राफस सहित अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रपत्र के भाग-11 पर अपनी पात्रता सत्यापित करवा कर सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलॉन्ज, शिमला-171012 को प्रेषित करें जोकि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10-10-2009 तक पहुंच जाने चाहिए ।

आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति भी सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड को भेजी जा सकती है । आवेदन पत्र तथा समय सारणी HIPA वैबसाईट [himachal.nic.in/hipa](http://himachal.nic.in/hipa) से डाउनलोड अथवा आवेदन पत्र को टंकित व फोटोस्टैट भी करवाया जा सकता है ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
सचिव,।

**H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, HIPA-FAIRLAWNS, SHIMLA-12**  
**DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, NOVEMBER, 2009**

**DATE SHEET**

**IAS/HAS**

| Sr.No | Date/Day                | Time                               | IAS Papers  | HAS Papers  |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1.    | 05.11.2009<br>Thursday  | 10 AM to 1 PM                      | Criminal Law & Procedure<br>(Paper-1)                       | Criminal Law & procedure<br>(Paper-1)                       |
|       |                         | 2 PM to 5 PM                       | Criminal Case<br>(Paper-2)                                  | Criminal Case<br>(Paper-2)                                  |
| 2.    | 06.11.2009<br>Friday    | 10 AM to 1 PM                      | Revenue Law &<br>Procedure<br>(Paper-3)                     | Revenue Law & Procedure<br>(Paper-3)                        |
|       |                         | 2 PM to 5 PM                       | Revenue Case<br>(Paper-5)                                   | Revenue Case<br>(Paper-5)                                   |
| 3.    | 07.11.2009<br>Saturday  | 10 AM to 1 PM                      |   | General Administration<br>(Paper-6)                         |
|       |                         | 2 PM to 3.30 PM                    | Hindi (written)   | Hindi (written)   |
|       |                         | 3.30 PM to 5 PM                    | Hindi (Oral) (Paper-4)                                      | Hindi (Oral) (Paper-4)                                      |
| 4.    | 09.11.2009<br>Monday    | 10 AM to 1 PM                      |   | Planning & Development<br>(Paper-7)                         |
|       |                         | 2 PM to 5 PM                       |   | Constitution & Civil Law<br>(Paper-8)                       |
| 5.    | 10.11.2009<br>Tuesday   | 10 AM to 1 PM                      | Civil Services Treasury<br>and Financial Rules<br>(Paper-9) | Civil Services Treasury and<br>Financial Rules<br>(Paper-9) |
|       |                         | 2 PM to 5 PM                       | Special Acts (Criminal)<br>Manuals & Rules<br>(Paper-10)    | Special Acts (Criminal)<br>Manuals & Rules<br>(Paper-10)    |
| 6.    | 11.11.2009<br>Wednesday | 10 AM to 1 PM                      | Minor (Revenue) Acts &<br>Manuals (Paper-11)                | Minor (Revenue) Acts &<br>Manuals (Paper-11)                |
|       |                         | 2 PM to 3.30 PM<br>4 PM to 5.00 PM |   | Computer (Written)<br>(Practical) (Paper-14)                |
| 7.    | 12.11.2009<br>Thursday  | 10 AM to 11.30 PM                  | Motor Mechanism &<br>Driving (Written)                      | Motor Mechanism &<br>Driving (Written)                      |
|       |                         | 12.15 PM to 5 PM                   | Practical<br>(Paper-12)                                     | Practical<br>(Paper-12)                                     |
| 8.    | 13.11.2009<br>Friday    | 10.00 AM to 5 PM                   |   | Target Shooting (Rifle &<br>Revolver)<br>(Paper-13)         |

**NOTE:**

**VENUE: 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2**  
**2. Computer Practical at HIPA**

**TEHSILDARS/ NAIB-TEHSILDARS**

| <b>Sr. No</b> | <b>Date/Day</b>         | <b>Time</b>     | <b>Tehsildars Papers</b>                               | <b>Naib-Tehsildars Papers</b>                      |
|---------------|-------------------------|-----------------|--|--|
| 1.            | 07.11.2009<br>Saturday  |                 |  |  |
|               |                         | 2 PM to 3.30 PM | Hindi (written)  | Hindi (written)                                    |
|               |                         | 3.30 PM to 5 PM | Hindi (Oral)<br>(Paper-4)                              | Hindi (Oral)<br>(Paper-4)                          |
| 2.            | 09.11.2009<br>Monday    | 10 AM to 1 PM   | Land Revenue Acts & Rules<br><br>(Paper-1)             | Land Revenue Acts & Rules<br><br>(Paper-1)         |
|               |                         | 2 PM to 5 PM    | Arithmetic & Patwaris Mensuration<br><br>(Paper-2)     | Arithmetic & Patwaris Mensuration<br><br>(Paper-2) |
|               |                         |                 |  |  |
| 3.            | 10.11.2009<br>Tuesday   | 10 AM to 1 PM   | Minor Revenue Acts & Rules<br><br>(Paper-3)            | Minor Revenue Acts & Rules<br><br>(Paper-3)        |
|               |                         | 2 PM to 5 PM    | Criminal Law & Procedure<br><br>(Paper-5)              | Criminal Law & Procedure<br><br>(Paper-5)          |
|               |                         |                 |  |  |
| 4.            | 11.11.2009<br>Wednesday | 10 AM to 1 PM   | Revenue Case<br><br>(Paper-6)                          |  |
|               |                         | 2 PM to 5 PM    | Local & Special Law<br><br>(Paper-7)                   |  |
|               |                         |                 |  |  |
| 5.            | 12.11.2009<br>Thursday  | 10 AM to 1 PM   | Local Fund Treasury & Financial Rules<br><br>(Paper-8) |  |

**NOTE:-****VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2**

**TECHNICAL / NON-TECHNICAL DEPARTMENTS**

| Sr. No | Date/Day               | Time             | Technical Papers   | Non-Technical Papers                      |
|--------|------------------------|------------------|--|---|
| 1.     | 05.11.2009<br>Thursday | 10 AM to 1 PM    | Financial Administration<br><br>(Paper_1)<br>(Only for Principals/<br>eligible Lecturers/<br>Headmasters and<br>eligible Teachers of<br>Education Deptt. | -   |
|        |                        | 2 PM to 5 PM     | Financial Administration<br><br>(Paper-1)  | Financial Administration<br><br>(Paper-1) |
| 2.     | 06.11.2009<br>Friday   | 10 AM to 1 PM    | Concerned Departments<br><br>(Paper-3)   | Concerned Departments<br><br>(Paper -3)   |
|        |                        | 2 PM to 5 PM     | -  | Concerned Departments<br><br>(Paper-4)    |
| 3.     | 07.11.2009<br>Saturday | 10 AM to 1 PM    | -  | Concerned Departments (Paper-5)           |
|        |                        | 10 AM to 11.30AM |  | Panch Raj-Computer<br>(Written)(Paper-5)  |
|        |                        | 12 Noon to 1 PM  |  | Panch Raj-Computer<br>(Practical)         |
|        |                        | 2 PM to 3.30 PM  | Hindi (written)  | Hindi (written)                           |
|        |                        | 3.30 PM to 5 PM  | Hindi (Oral)<br>(Paper-2)  | Hindi (Oral)<br>(Paper-2)                 |

**NOTE:-****VENUE: 1. H. P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2****2. MANDI AND DHARAMSHALA FOR FINANCIAL ADMINISTRATION ONLY****3. Computer Practical at HIPA**

**NON-TECHNICAL DEPARTMENT (TREASURY AND DISTT. TREASURY OFFICERS)**

| Sr. No | Date/Day               | Time                | Non-Technical Papers                                     |
|--------|------------------------|---------------------|--|
| 1.     | 05.11.2009<br>Thursday | 10 AM to 1 PM       | -  |
|        |                        | 2 PM to 5 PM        | Financial Rules<br>(Paper-5)                             |
| 2.     | 06.11.2009<br>Friday   | 10 AM to 1 PM       | Principles of Accounts<br>(Paper -3)                     |
|        |                        | 2 PM to 5 PM        | Treasury Rules and Accounting<br>Procedures<br>(Paper-4) |
| 3.     | 07.11.2009<br>Saturday | 10 AM to 12 NOON    | I.T. (Written)   |
|        |                        | 12.30 PM to 1.30 PM | I.T. (Practical)<br>(Paper-1)                            |
|        |                        | 2 PM to 3.30 PM     | Hindi (written)  |
|        |                        | 3.30 PM to 5 PM     | Hindi (Oral)<br>(Paper-2)                                |

**NOTE:-**

**VENUE: 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2**  
**2. I.T. Practical at HIPA**

**EXCISE & TAXATION INSPECTORS**

| Sr. No | Date/ Day               | Time          | Paper Name /Paper Number                                    |
|--------|-------------------------|---------------|---|
| 1.     | 09.11.2009<br>Monday    | 10 AM to 1 PM | Law of Crimes<br>(Paper-1)                                  |
|        |                         | 2 PM to 5 PM  | Excise Law<br>(Paper-2)                                     |
| 2.     | 10.11.2009<br>Tuesday   | 10 AM to 1 PM | Law Relating to Allied Taxes<br>(Paper-3)                   |
|        |                         | 2 PM to 5 PM  | Sales Tax Law & Practices<br>(Paper-4)                      |
| 3.     | 11.11.2009<br>Wednesday | 10 AM to 1 PM | Book Keeping & General Commercial<br>Knowledge<br>(Paper-5) |

**NOTE:-**

**VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002.**



**BOARDS/CORPORATIONS****DATE SHEET**

| Sr. No | Date       | Day      | Time          | EDUCATION BOARD                         |
|--------|------------|----------|---------------|---|
| 1.     | 05-11-2009 | Thursday | 2 PM to 5 PM  | Financial Administration<br>(Paper-1)   |
| 2.     | 06.11.2009 | Friday   | 10 AM to 1 PM | Administration and General<br>(Paper-2) |
| 3.     | 07.11.2009 | Saturday | 10 AM to 1 PM | Board Act and Regulations<br>(Paper-3)  |

**NOTE:-**

**VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002.**

**Assistant Engineers/Engineering Officers of H.P. State Electricity Board**

| Sr. No | Date/ Day             | Time          | Paper Name /Paper Number  |
|--------|-----------------------|---------------|---|
| 1.     | 09.11.2009<br>Monday  | 10 AM to 1 PM | Works, Store and Commercial<br>Accounts/ Manuals.<br>(Paper-1)                              |
| 2.     | 10.11.2009<br>Tuesday | 10 AM to 1 PM | Financial Rules, Budget, Service<br>Regulations, Acts and Office<br>Procedure.<br>(Paper-2) |

**NOTE:-**

**VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002.**

**INDUSTRIES DEPARTMENT****NOTIFICATION**

*Shimla-2 the 6th August, 2009*

**No. Ind-A(A)9-1/2008 .**—In partial modification of this Department's notification of even No. dated 20-2-2008 regarding constitution of Board of Directors of H.P. State Industrial

Development Corporation Ltd. and in exercise of the powers conferred *vide* section 82 of Memorandum of Articles of Association of H.P. State Industrial Development Corporation Ltd. the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate Shri Kishan Kapoor, Hon'ble Industries Minister as Chairman of the H.P. State Industrial Development Corporation in place of Shri Prem Kumar Dhumal, Hon'ble Chief Minister from the date of assuming the charge as Industries Minister.

By Order,  
Sd/-  
*Principal Secretary.*

---